



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241।

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2005/ज्येष्ठ 17, 1927

No. 241।

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2005/JYAISTA 17, 1927

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 15/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 357(अ)।—वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 88 के खंड (क) तथा खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के उक्त खंडों के उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख 16 जून, 2005 नियत करती है।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 15/2005-Service Tax

G. S. R. 357(E)।—In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (b) of Section 88 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005), the Central Government hereby appoints the 16th day of June, 2005 as the date on which the provisions of the said clauses of the said Act shall come into force.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 16/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 358(अ)।—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की

1734 GI/2005

धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा पत्तन एवं अन्य पत्तन के निर्माण के संबंध में वाणिज्यिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाई गई, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खण्ड (य य थ) के अंतर्गत आने वाली वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के तहत उन पर उद्यगात्मक संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रभावी होगी।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 16/2005-Service Tax

G. S. R. 358(E)।—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the commercial or industrial construction service, referred to in sub-clause (zzq) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, provided to any person by a commercial concern in relation to construction of port or other port, from the whole of service tax leviable thereon under Section 66 of the said Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 17/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 359(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा सड़कों, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों, बांधों, पत्तनों एवं अन्य पत्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाई गई, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खण्ड (य य य क) के अंतर्गत आने वाली कार्यस्थल निर्माण एवं सफाई, खुदाई तथा मिट्टी हटाई एवं ध्वंस सेवा को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के तहत उन पर उद्ग्राह्य संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रभावी होगी।

[फा. सं. शी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 17/2005-Service Tax

**G. S. R. 359(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the site formation and clearance, excavation and earthmoving and demolition and such other similar activities, referred to in sub-clause (zzza) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, provided to any person by any other person in the course of construction of roads, airports, railways, transport terminals, bridges, tunnels, dams, ports or other ports, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 18/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 360(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खण्ड (यययज) में उल्लिखित, कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करवाई गई

कराधेय सेवा को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के तहत उस पर उद्ग्राह्य उतने सेवा कर से छूट प्रदान करती है जो उस मूल्य पर परिकलित किये गए सेवा कर से अधिक है जो ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा किसी व्यक्ति से उक्त कराधेय सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारित की गई सकल राशि के तीनोंस प्रतिशत के बराबर है:

ताकि यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां-

- (i) सेनेटेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के तहत ऐसी कराधेय सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयुक्त की गई निविष्टियों अथवा पूँजीगत माल पर चुकाए गए शुल्क का क्रेडिट लिया गया है; अथवा
- (ii) सेवा प्रदाता ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2003-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2003 { सा.का.नि. 503 (अ), दिनांक 20 जून, 2003) के तहत लाभ उठाया है; अथवा
- (iii) वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (30क) के उप-खण्ड (ख) में उल्लिखित आवासीय काम्पलैक्स के संबंध में उपलब्ध करवाई गई कराधेय सेवाएं मात्र समाप्त एवं परिष्करण सेवाएं हैं।

**स्पष्टीकरण :-** इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "प्रभारित सकल राशि" में उक्त सेवा प्रदाता द्वारा उक्त कराधेय सेवा उपलब्ध करवाने के लिए आपूर्ति किये गए अथवा उपलब्ध करवाए गए अथवा प्रयुक्त किए गए माल तथा सामग्री का मूल्य शामिल होगा ।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रभावी होगी।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 18/2005-Service Tax

**G. S. R. 360(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service provided to any person by any other person, in relation to construction of complex, referred to in sub-clause (zzzh) of clause (105) of section 65 of the Finance Act, from so much of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, as is in excess of the service tax calculated on a value which is equivalent to thirty-three per cent. of the gross amount charged from any person by such service provider for providing the said taxable service:

Provided that this exemption shall not apply in such cases where –

- (i) the credit of duty paid on inputs or capital goods used for providing such taxable service has been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004; or
- (ii) the service provider has availed the benefit under the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 12/2003-Service Tax, dated the 20th June, 2003 [G.S.R. 503 (E), dated the 20th June, 2003]; or
- (iii) the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to residential complex, referred to in sub-clause (b) of clause (30a) of section 65 of the Finance Act.

*Explanation.-* For the purposes of this notification, the “gross amount charged” shall include the value of goods and materials supplied or provided or used for providing the said taxable service by the said service provider.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-I/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 7 जून, 2005  
सं. 19/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 361(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस बात का समाधान हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं उक्त सारणी के कॉलम (3) में सदृश प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए तरीके से संशोधित अथवा और आगे संशोधित जैसा भी मामला हो, की जाएंगी, नामतः -

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. एवं तिथि	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	13/2003-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2003 [सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 20 जून, 2003]	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खण्ड(i) हटा दिया जाएगा ।
2.	14/2004-सेवा कर, दिनांक 10 सितंबर, 2004 [सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 10 सितंबर, 2004]	उक्त अधिसूचना में,-- (i) खण्ड(ख) में, "ग्राहक की ओर से माल का उत्पादन" शब्दों की जगह "ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से माल का उत्पादन अथवा प्रसंस्करण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) "संपूर्ण सेवा कर से" शब्दों की जगह "और कृषि, मुद्रण, वस्त्र संसाधन अथवा शिक्षा के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सेवा को संपूर्ण सेवा कर से" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । (iii) परन्तुक हटा दिया जाएगा ।
3.	15/2004-सेवा कर, दिनांक 10 सितंबर, 2004	उक्त अधिसूचना में,- (i) दो जगह पर आने वाले "निर्माण सेवा" शब्दों की जगह "वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

		<p>(ii) परन्तुक में, खण्ड(ii) की जगह , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-</p> <p>"(ii) वाणिज्यिक संस्था द्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 जून, 2003 की अधिसूचना सं. 12/2003- सेवा कर {सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 20 जून, 2003} के तहत लाभ उठाया गया है; अथवा</p> <p>(iii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (25 ख) के उप-खण्ड (ग) में उल्लिखित, भवन अथवा सिविल ढांचे के संबंध में उपलब्ध करवाई गई कराधीय सेवाएं मात्र समापन एवं परिष्करण सेवाएं हैं।"</p>
4.	24/2004-सेवा कर, दिनांक 10 सितंबर, 2004 [सा.का.नि. 598(अ), दिनांक 10 सितंबर, 2004]	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शुरुआती पैरा में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-</p> <p>"बशर्ते कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग के संबंध में उपलब्ध करवाई गई कराधीय सेवाओं पर इस अधिसूचना में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।;"</p> <p>(ii) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-</p> <p>"(iii)"कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान" का अर्थ है वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग केन्द्र जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर संबंधी कोचिंग अथवा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है।"।</p>
5.	8/2005-सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2005 [सा.का.नि. 142(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005]	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) "ग्राहक की ओर से माल का उत्पादन "शब्दों की जगह "ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से माल का उत्पादन अथवा प्रसंस्करण " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;</p> <p>(ii) परन्तुक में दो स्थानों पर आने वाले "उत्पादित " शब्द की जगह "उत्पादित अथवा प्रसंस्कृत" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;</p> <p>(iii) स्पष्टीकरण में, खण्ड (i) में, (क)" माल का उत्पादन" शब्दों की जगह "माल</p>

		का उत्पादन अथवा प्रसंस्करण" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; (ख) दो स्थानों पर आने वाले "उत्पादन" शब्द की जगह "उत्पादन अथवा प्रसंस्करण" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
--	--	--

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रभावी होगी ।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी :

- (1) मूल अधिसूचना सं. 13/2003- सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं.504 (अ), दिनांक 20 जून, 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 8/2004- सेवा कर, दिनांक 9 जुलाई, 2004 (सा.का.नि.434(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2004) के तहत संशोधित किया गया था;
- (2) मूल अधिसूचना सं. 14/2004- सेवा कर, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि.सं.588 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी;
- (3) मूल अधिसूचना सं. 15/2004- सेवा कर, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं.589 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 4/2005- सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2005 (सा.का.नि.138(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005) के तहत संशोधित किया गया था ;
- (4) मूल अधिसूचना सं. 24/2004- सेवा कर, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि.सं.598 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी ;
- (5) मूल अधिसूचना सं. 8/2005- सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि.सं.142 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 19/2005-Service Tax

**G. S. R. 361(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) as specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

## TABLE

S.No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	13/2003-Service Tax, dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003 [G.S.R. 504 (E), dated the 20 <sup>th</sup> June, 2003]	In the said notification, in the <i>Explanation</i> , clause (i) shall be omitted.
2.	14/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 588 (E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004]	In the said notification,- (i) in clause (b), for the words "production of goods on behalf of the client;" the words "production or processing of goods for, or on behalf of, the client;" shall be substituted; (ii) for the words "from the whole of the service tax", the words "and provided in relation to agriculture, printing, textile processing or education, from the whole of service tax" shall be substituted; (iii) the proviso shall be omitted.
3.	15/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 589 (E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004]	In the said notification,- (i) for the words "construction service", occurring at two places, the words "commercial or industrial construction service" shall be substituted; (ii) in the proviso, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:- "(ii) the commercial concern has availed the benefit under the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 12/2003-Service Tax, dated the 20th June, 2003 [G.S.R. 503 (E), dated the 20th June, 2003]; or (iii) the taxable services provided are only completion and finishing services in relation to building or civil structure, referred to in sub-clause (c) of clause (25b) of section 65 of the Finance Act, 1994.".
4.	24/2004-Service Tax, dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004 [G.S.R. 598 (E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 2004]	In the said notification,- (i) in the opening paragraph, the following proviso shall be inserted at the end, namely:- "Provided that nothing contained in this notification shall apply to the taxable services

		<p>(ii) provided in relation to commercial training or coaching by a computer training institute.”;</p> <p>in the <i>Explanation</i>, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-</p> <p>‘(iii) “computer training institute” means a commercial training or coaching centre which provides coaching or training relating to computer software or hardware.’</p>
5.	8/2005-Service Tax, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R. 142 (E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2005]	<p>In the said notification,-</p> <p>(i) for the words “production of goods on behalf of the client”, the words “production or processing of goods for, or on behalf of, the client” shall be substituted;</p> <p>(ii) in the proviso, for the words “produced”, occurring at two places, the words “produced or processed” shall be substituted;</p> <p>(iii) in the <i>Explanation</i>, in clause (i),-</p> <p>(a) for the words ‘“production of goods”’, the words ‘“production or processing of goods”’ shall be substituted;</p> <p>(b) for the words “production” occurring at two places, the words “production or processing” shall be substituted.</p>

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note :**

- (1) The principal notification 13/2003-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 504 (E) dated the 20<sup>th</sup> June, 2003 and was last amended *vide* notification No. 8/2004-Service Tax, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 [G.S.R. 434 (E) dated the 9<sup>th</sup> July, 2004];
- (2) The principal notification 14/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 588 (E) dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (3) The principal notification 15/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 589 (E) dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 and was last amended *vide* notification No. 4/2005-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R. 138 (E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2005];
- (4) The principal notification 24/2004-Service Tax, dated the 10<sup>th</sup> September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 598 (E) dated the 10<sup>th</sup> September, 2004;
- (5) The principal notification 8/2005-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 142 (E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 7 जून, 2005  
सं. 20/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 362(अ).—वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा आवश्यक है एतद्वारा नीचे सारणी के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नवत अधिसूचनाओं, ऐसे रद्द करने से पहले की गई अथवा विलोपित की जाने वाली संबंद्ह वस्तुओं को छोड़कर, को रद्द करती है, अर्थात्

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख
1.	6/2001-सेवाकर, दिनांक 9 जुलाई, 2001 (सा.का.नि.516(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2001)
2.	7/2001-सेवाकर, दिनांक 9 जुलाई, 2001 (सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2001)
3.	11/2002-सेवाकर, दिनांक 1 अगस्त, 2002 (सा.का.नि.539(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2002)
4.	18/2003-सेवाकर, दिनांक 21 अगस्त, 2003 (सा.का.नि.676(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2003)

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[ फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू. ]

अजय, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 20/2005-Service Tax

**G. S. R. 362(E).**— In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:—

173461/05—२

## TABLE

S.No.	Notification No. and date
(1)	(2)
1.	6/2001-Service Tax, dated the 9 <sup>th</sup> July, 2001 [G.S.R. 516 (E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2001]
2.	7/2001-Service Tax, dated the 9 <sup>th</sup> July, 2001 [G.S.R. 517 (E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2001]
3.	11/2002-Service Tax, dated the 1 <sup>st</sup> August, 2002 [G.S.R. 539 (E), dated the 1 <sup>st</sup> August, 2002]
4.	18/2003-Service Tax, dated the 21 <sup>st</sup> August, 2003 [G.S.R. 676 (E), dated the 21 <sup>st</sup> August, 2003]

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 21/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 363(अ).— वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32), (इसके बाद वित्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इस बात से संतुष्ट होने पर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (19) के उपखण्ड (V) में उल्लिखित मुवकिल के लिए अथवा उसकी तरफ से माल के उत्पादन अथवा संसाधन के लिए कराधीय सेवा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले (क) कटाई और पालिश किये गये हीरे और बहुमूल्य पत्थर: अथवा (ख) सोने और अन्य मूल्यवान धातुओं की सादे और जड़ित आभूषण के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान ऐसे मुवकिल को किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के द्वारा प्रदान की गयी हो, को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवाकर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रवृत्त होगी।

[फा. स. बी-1/5/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 21/2005-Service Tax

**G. S. R. 363(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of production

or processing of goods for, or on behalf of, the client, referred to in sub-clause (v) of clause (19) of section 65 of the said Finance Act, provided by a commercial concern, in the course of manufacture of,-

(a) cut and polished diamonds and gem stones; or  
" gold and other precious metals,

Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of service tax  
ct.

far  
lev

For

CL/1

2.

16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/5/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

IS

अधिसूचना

राई दिल्ली, 7 जून, 2005

म. 22/2005-सेवा कर

3

15/2005

7-7-05

है

1, 1994 (1994 का 32) (इसमें इसके पश्चात् वित्त की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा वित्त खण्ड (ज) (झ) (झ), (य ह), (य द), (य यक), (य यछ), यें जो किसी अनिवासी व्यक्ति के द्वारा किसी जहाज के

8 का 44) के अंतर्गत किसी भारतीय जहाज के रूप में

पंजीकृत हा;

(ख) तटीय जलयान अधिनियम, 1838 (1838 का 19);

(ग) अंतर्रेशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1); अथवा

(घ) वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के अंतर्गत चार्टेड और पंजीकृत हो, और ऐसा जहाज (क) किसी भारत के नागरिक (ख) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी अथवा निकाय जिसका अपने कारोबार का प्रमुख स्थान भारत में हो; अथवा

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 अथवा किसी राज्य में उस समय प्रवृत्त होने के कारण सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अन्य किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा पंजीकृत माना गया हो, के स्वामित्व में हो अथवा सनदी हो, जैसा भी मामला हो, को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवाकर से छूट प्रदान करती है।

बशर्ते कि उक्त छूट ऐसे मामलों में ही लागू होगी जहाँ उक्त कराधेय सेवाएं

(क) भारत से बाहर किसी पत्तन में जहाज के कार्य के निपटान;

(ख) भारत से बाहर किसी पत्तन में किसी जहाज में लाये गये माल के निपटान अथवा भण्डारण; अथवा

(ग) जहाजों के कार्य के निपटान अथवा किसी जहाज में लाये गये माल से संबंधित अन्य किसी सेवा के संबंध में प्रदान की गई हों।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "अनिवासी व्यक्ति" का आशय कोई व्यक्ति जिसने कोई कारोबार स्थापित किया हो अथवा कोई स्थिर स्थापन है जिससे सेवा प्रदान की गई है अथवा प्रदान की जानी है अथवा भारत को छोड़कर अन्य देश में अपना स्थाई पता अथवा सामान्य आवास स्थान है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 से प्रभावी होगी।

[ फा. सं. बी-1/7/2005-टी. आर. यू. ]

अजय, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 22/2005-Service Tax

**G. S. R. 364(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services specified in sub-clauses (h), (i), (j), (zn), (zr), (zza), (zzg), (zzi) and (zzl) of clause (105) of section 65 of the Finance Act provided by a non-resident person outside India and consumed outside India, in the course of sailing of a ship which is,-

- (a) registered as an Indian ship under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
- (b) registered under the Coasting Vessels Act, 1838 (19 of 1838);
- (c) registered under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917); or
- (d) chartered and licenced under the Merchant Shipping Act, 1958,

and such ship is owned or chartered, as the case may be, by,-

- (i) a citizen of India;
- (ii) a company or a body established by or under any Central Act or State Act which has its principal place of business in India; or
- (iii) a co-operative society which is registered or deemed to be registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or any other law relating to co-operative societies for the time being in force in any State,

from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act:

Provided that the said exemption shall apply only in such cases where the said taxable services are provided in relation to,-

- (a) handling of ships in a port outside India;
- (b) handling or storage of goods carried in a ship in a port outside India; or
- (c) any other services related to the handling of ships or goods carried in a ship.

*Explanation.*— For the purposes of this notification, “non-resident person” means a person, who has established a business or has a fixed establishment from which the service is provided or to be provided, or has his permanent address or usual place of residence, in a country other than India.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/7/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 23/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 365(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारायें (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नवत नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों सेवाकर (पाँचवां संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाये।
- (2) ये 16 जून, 2005 से प्रवृत्त होंगे।

2. सेवाकर नियमावली, 1994 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खण्ड (घ) में,

(i) उपखण्ड (iv) के स्थान पर निम्नवत उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(iv) किसी व्यक्ति जिसका कोई स्थापित कारोबार हो अथवा स्थिर स्थापन हो जिससे सेवा प्रदान की जाती हो अथवा प्रदान की जानी हो अथवा भारत को छोड़कर अन्य किसी देश में अपना स्थाई पता अथवा सामान्य निवासी स्थान हो, के द्वारा प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली किसी कराधीय सेवा के संबंध में और ऐसा सेवा प्रदाता का भारत में कोई कार्यालय न हो, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सेवा प्राप्त करता है और भारत में अपना कारोबार का स्थान, स्थिर स्थापन, स्थाई पता अथवा सामान्य आवास स्थान हो, जैसा भी मामला हो "

(ii) उपखण्ड (V) में, मद (ख) में, "के द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित" शब्दों के स्थान पर "के अंतर्गत बनाया गया अथवा पंजीकृत" शब्द प्रति स्थापित किये जायेंगे ।

3. उक्त नियमावली में, नियम 4क में, उपनियम (1) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"बशर्ते यह भी कि जहां कराधीय सेवा के मूल्य के प्रति कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है और ऐसी कराधीय सेवा क्रमिक समय अवधियों के लिए सतत रूप से उपलब्ध करवाई जाती है तथा ऐसी कराधीय सेवा का मूल्य आवधिक रूप से नियत किया जाता है अथवा चुकाया जाता है तो ऐसी कराधीय सेवा उपलब्ध करवा रहे व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के अंतिम दिन से अधिक से अधिक चौदह दिन के अंदर बीजक, बिल अथवा जैसा भी मामला हो, चालान जारी किया जाएगा ।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 6 में, उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जायेगा अर्थात् :-

"(4क) उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी निर्धारिती ने इस नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत पंजीकरण का विकल्प लिया है और अपने अन्य परिसरों अथवा कार्यालयों पर कराधीय सेवाओं के मूल्य के प्रति प्राप्त भुगतानों का विवरण प्राप्त न होने के कारण से केन्द्रीय सरकार के खाते में उस राशि से अधिक राशि अदा की है जो एक माह अथवा तिमाही, जैसा भी मामला हो, की सेवा कर देयता के प्रति अदा की जानी अपेक्षित है तो निर्धारिती उसके द्वारा सेवा कर के रूप में अदा की गई इस अतिरिक्त राशि को परवर्ती अवधि के लिए उसकी सेवा कर देयता के प्रति समायोजित कर सकता है और ऐसे समायोजन का विवरण ऐसे समायोजन की तिथि के पन्द्रह दिन के अंदर क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को सूचित किया जाएगा ।"

[ फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू. ]

अजय, अबर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना सं. 2/94-सेवाकर, दिनांक 28 जून, 1994 के तहत अधिसूचित और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 546(अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत प्रकाशित किये गये थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 7/2005-सेवाकर, दिनांक 1 मार्च, 2005 जो सा.का.नि.सं.141 (अ) दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किये गये थे ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 23/2005-Service Tax

**G. S. R. 365(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Fifth Amendment) Rules, 2005.  
 (2) They shall come into force on the 16th day of June, 2005.
2. In the Service Tax Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d),—  
 (i) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:—  
 “(iv) in relation to any taxable service provided or to be provided by a person, who has established a business or has a fixed establishment from which the service is provided or to be provided, or has his permanent address or usual place of residence, in a country other than India, and such service provider does not have any office in India, the person who receives such service and has his place of business, fixed establishment, permanent address or, as the case may be, usual place of residence, in India;”;  
 (ii) in sub-clause (v), in item (b), for the words “established by or under”, the words “formed or registered under” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 4A, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—  
 “Provided also that where any payment towards the value of taxable service is not received and such taxable service is provided continuously for successive periods of time and the value of such taxable service is determined or payable periodically, an invoice, a bill, or as the case may be, a challan shall be issued by a person providing such taxable service, not later than fourteen days from the last day of the said period.”.
4. In the said rules, in rule 6, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—  
 “(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), where an assessee has opted for registration under sub-rule (2) of rule 4 of these rules and has paid to the credit of Central Government any amount in excess of the amount required to be paid towards service tax liability for a month or quarter, as the case may be, for the reason of not receiving details of payments received towards the value of taxable services at his other premises or offices, the assessee may adjust such excess amount so paid as service tax by him against his service tax liability for the subsequent period and the details of such adjustment shall be intimated to the jurisdictional Superintendent of Central Excise within a period of fifteen days from the date of such adjustment.”.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:** The principal rules were notified *vide* notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R.546 (E), dated the 28th June 1994 and were last amended *vide* notification No. 7/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005 which was published *vide* number G.S.R. 141(E), dated the 1st March, 2005.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 24/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 366(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2004-सेवाकर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 849 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नवत संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैराग्राफ (क) में, उप पैराग्राफ (iv) में, मद (ख) में " के द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित किये गये" शब्दों के स्थान पर " के अंतर्गत बनाये गये अथवा पंजीकृत " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) पैराग्राफ (ख) के स्थान पर निम्नवत पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" किसी व्यक्ति जिसने कोई कारोबार स्थापित किया हो अथवा कोई स्थिर स्थापन हो जिससे सेवा प्रदान की जाती हो अथवा प्रदान की जानी हो अथवा भारत को छोड़कर अन्य किसी देश में अपना स्थाई पता अथवा आवास का सामान्य स्थान हो, के द्वारा प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली कोई करार्धेय सेवा और ऐसे सेवा प्रदाता का भारत में कोई कार्यालय नहीं हो"

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 को प्रवत्त होगी ।

[ फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू. ]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 36/2004-सेवाकर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 में सा.का.नि. 849(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार दिनांक 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 5/2005-सेवाकर (सा.का.नि.139 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2005) के तहत संशोधित किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 24/2005-Service Tax

**G. S. R. 366(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph (A), in sub-paragraph (iv), in item (b), for the words "established by or under", the words "formed or registered under" shall be substituted;

(ii) for paragraph (B), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“any taxable service provided or to be provided by a person, who has established a business or has a fixed establishment from which the service is provided or to be provided, or has his permanent address or usual place of residence, in a country other than India, and such service provider does not have any office in India.”.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st December, 2004 *vide* number G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004 and was last amended *vide* notification No. 5/2005-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R. 139 (E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2005];

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 25/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 367(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा किसी सेवादाता द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई कराधेय सेवाओं को जहाँ उक्त कराधेय सेवायें ऐसे व्यष्टि द्वारा वाणिज्य अथवा उद्योग अथवा अन्य किसी कारोबार के कार्य के दौरान अथवा बढ़ोतरी को छोड़कर, भारत से बाहर प्राप्त किया जाता है अथवा उपयोग में लिया जाता है, को वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत इस पर लगने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 25/2005-Service Tax

**G. S. R. 367(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts any taxable service provided to an individual by a service provider, where the said taxable services are received and consumed outside India, by such individual, not in the course or furtherance of commerce or industry or any other business, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act.

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 7 जून, 2005  
सं. 26/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 368(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 69 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नवत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग जो उक्त उपधारा के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, को विनिर्दिष्ट करती हैं, नामशः—

- (i) कोई निविष्ट सेवा वितरक; और
- (ii) कराधीय सेवा का कोई प्रदाता जिसकी किसी वित्त वर्ष में कराधीय सेवा का कुल मूल्य तीन लाख रुपये से अधिक हो।

स्पष्टीकरण-1:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ जहां किसी कराधीय सेवा का प्रदाता एक अथवा उससे अधिक परिसरों से एक अथवा उससे अधिक कराधीय सेवायें प्रदान करते हैं, ऐसी सभी परिसरों से ऐसी सभी कराधीय सेवाओं प्रत्येक सेवा अथवा प्रत्येक परिसर से अलग-अलग नहीं, के कुल मूल्य को कराधीय सेवा की कुल मूल्य की संगणना में शामिल किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-2:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ;—

(क) "निविष्ट सेवा वितरक" का आशय सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2 के खण्ड (ड) में निर्धारित किये गये अनुसार है;

(ख) "कराधीय सेवा के कुल मूल्य" का आशय उक्त वित्त अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत विहित किये गये अनुसार कराधीय सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा किसी वित्त वर्ष के दौरान प्रभारित सकल राशि के लिए प्राप्त कुल राशि के प्रथम क्रमिक भुगतान, लेकिन ऐसी सकल राशि जिसे दिनांक 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर (सा.का.नि. 140(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005) को छोड़कर किसी अधिसूचना के अंतर्गत उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उस पर लगने वाले सम्पूर्ण सेवाकर से छूट दी गई है, के लिए प्राप्त भुगतान शामिल नहीं है, से है।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]  
अजय, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 26/2005-Service Tax

**G. S. R. 368(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby specifies the following person or class of persons who shall make an application for registration under the provisions of the said sub-section, namely:-

- (i) an input service distributor; and
- (ii) any provider of taxable service whose aggregate value of taxable service in a financial year exceeds three lakh rupees.

*Explanation 1.*— For the purposes of this clause, where a provider of taxable service provides one or more taxable services from one or more premises, the aggregate value of all such taxable services and from all such premises and not separately for each services or each premises shall be taken into account for computation of aggregate value of taxable service.

*Explanation 2.- For the purposes of this notification,-*

- (a) "input service distributor" has the meaning assigned to it in clause (m) of rule 2 of the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (b) "aggregate value of taxable service" means the sum total of first consecutive payments received during a financial year towards the gross amount, as prescribed under section 67 of the said Finance Act, charged by the service provider towards taxable services but does not include payments received towards such gross amount which are exempt from the whole or service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act under any notification other than Notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R. 140 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005].

2. This notification shall come into force on the 16th day of June, 2005.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 27/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 369(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ- (1) इन नियमों को सेवा कर (विशेष श्रेणी के व्यक्तियों का पंजीकरण) नियमावली, 2005 कहा जाए।  
(2) ये 16 जून, 2005 को प्रभावी होंगे।
2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;  
(क) "अधिनियम" का अर्थ है वित्त अधिनियम, 1944 (1944 का 32);  
(ख) "कराधेय सेवा का कुल मूल्य" का अर्थ है सेवा प्रदाता द्वारा कराधेय सेवाओं के लिए प्रभारित की गई, इस अधिनियम की धारा 67 के तहत यथा निर्धारित, कुल राशि के प्रति एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त प्रथम क्रमिक भुगतानों की कुल राशि लेकिन इसमें ऐसी सकल राशि के प्रति प्राप्त भुगतान शामिल नहीं है जिन्हें 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर {सा.का.नि.140(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005}को छोड़कर किसी अधिसूचना के तहत इस अधिनियम की धारा 66 के तहत उन पर उद्ग्रह्य संपूर्ण सेवा कर से छूट प्राप्त है।  
(ग) "निविष्टि सेवा वितरक" का वही अर्थ होगा जो इसे सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2 के खंड (ड) में दिया गया है।
3. पंजीकरण:- (1) निविष्टि सेवा प्रदाता व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि के तीस दिन की अवधि के अंदर अथवा 16 जून, 2005 तक, जो कोई भी बाद में हो, पंजीकरण हेतु बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये गए प्रपत्र में क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक आवेदन देगा।  
(2) कोई भी कराधेय सेवा जिसकी एक वित्तीय वर्ष की कराधेय सेवा का कुल मूल्य तीन लाख रुपये से अधिक हो जाता है वह कराधेय सेवा का कुल मूल्य तीन लाख रुपये से अधिक हो जाने के तीस दिन की अवधि के अंदर पंजीकरण हेतु बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये गए प्रपत्र में क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक आवेदन करेगा।

(3) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 के उप-नियम (2) से (7) के उपबंध उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों पर लागू होंगे जो ऐसे आशोधनों एवं परिवर्तनों, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं, सहित इन नियमों के उपबंधों के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करते हैं।

4. विवरणियां प्रस्तुत करना- निविष्टि सेवा वितरक सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 के उप-नियम (10) द्वारा निर्धारित किये गए प्रपत्र में तथा ऐसी बारंबारता पर क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 27/2005-Service Tax

**G. S. R. 369(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Service Tax (Registration of Special Category of Persons) Rules, 2005.  
 (2) They shall come into force on the 16th day of June, 2005.
2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—  
 (a) “Act” means the Finance Act, 1994 (32 of 1994);  
 (b) “aggregate value of taxable service” means the sum total of first consecutive payments received during a financial year towards the gross amount, as prescribed under section 67 of the Act, charged by the service provider towards taxable services but does not include payments received towards such gross amount which are exempt from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Act under any notification other than Notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005 [G.S.R. 140 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2005];  
 (c) “input service distributor” shall have the meaning assigned to it in clause (m) of rule 2 of the CENVAT Credit Rules, 2004.
3. **Registration.**— (1) The input service distributor shall make an application to the jurisdictional Superintendent of Central Excise in such form as may be specified, by notification, by the Board, for registration within a period of thirty days of the commencement of business or the 16th day of June, 2005, whichever is later.  
 (2) Any provider of taxable service whose aggregate value of taxable service in a financial year exceeds three lakh rupees shall make an application to the jurisdictional Superintendent of Central Excise in such form as may be specified, by notification, by the Board, for registration within a period of thirty days of exceeding the aggregate value of taxable service of three lakh rupees.  
 (3) The provisions of sub-rules (2) to (7) of rule 4 of Service Tax Rules, 1994 shall be applicable to the persons or class of persons who make an application for registration under the provisions of these rules, with such modifications and alterations as may be prescribed by the Board.
4. **Furnishing of returns.**— The input service distributor shall furnish a return to the jurisdictional Superintendent of Central Excise in such form and at such frequency as prescribed under sub-rule (10) of rule 9 of CENVAT Credit Rules, 2004.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]  
 AJAY. Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 28/2005-सेवा कर

सा. का. नि. 370(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेवा निर्यात नियमावली, 2005 को संशोधित करने के लिए निम्नवत नियम बनाती है, नामशः-

1. इन नियमों को सेवा निर्यात (संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाये ।

(2) ये 16 जून, 2005 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा निर्यात नियमावली, 2005 में, नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1),-

(क)" और (ययथ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर "(ययथ), (यययक), (यययख), (यययग) और (यययज)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द प्रति-स्थापित किये जायेंगे;

(ख) अंत में निम्नवत परन्तुक जोड़ा जायेगा, नामशः-

"बशर्ते कि इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, प्रदान की गई किसी कराधेय सेवाओं को तभी सेवाओं के निर्यात के रूप में समझा जायेगा यदि-

(क) ऐसी सेवा को भारत से बाहर प्रदान किया गया हो और भारत से बाहर कारोबार अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया गया हो; और

(ख) ऐसी प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा प्रदाता के द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया गया हो";

(ii) उपनियम (2) में,-

(क) "और (ययम)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "(ययम), (यययघ), (यययड) और (यययच)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) प्रथम परन्तुक के बाद, निम्नवत परन्तुक जोड़ा जायेगा, नामशः-

"बशर्ते कि इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, प्रदान की गई किसी कराधेय सेवाओं को तभी सेवाओं का निर्यात समझा जायेगा यदि-

(क) ऐसी सेवा भारत से बाहर प्रदान की गई हो और भारत से बाहर कारोबार अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली गई हो; और

(ख) प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया गया हो।";

(iii) उप नियम (3) में,-

(क) उपखण्ड (i) में "और (ययम)" शब्द कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर "(ययम), (यययक), (यययख), (यययघ), (यययड), (यययच) और (यययछ)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द प्रति स्थापित किये जायेंगे;

(ख) उपखण्ड (ii) में "घ" कोष्ठक, शब्द और अक्षरों के स्थान पर "(घ) और (यययग)" कोष्ठक, शब्द और अक्षर प्रति स्थापित किये जायेंगे ।

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 3 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 9/2005-सेवा कर के तहत अधिसूचित और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.151 (अ), दिनांक 3 मार्च, 2005 के तहत प्रकाशित किये गये थे ।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 28/2005-Service Tax

**G. S. R. 370(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Services Rules, 2005, namely :-

1. (1) These rules may be called the Export of Services (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the 16th day of June, 2005.
2. In the Export of Services Rules, 2005, in rule 3,-
  - (i) in sub-rule (1),-
    - (a) for the word, brackets and letters “and (zzq)”, the brackets, letters and word “, (zzq), (zzza), (zzzb), (zzzc) and (zzzh)” shall be substituted;
    - (b) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
 

“Provided that for the purposes of this sub-rule, any taxable services provided shall be treated as export of services only if-

      - (a) such service is delivered outside India and used in business or for any other purpose outside India; and
      - (b) payment for such service provided is received by the service provider in convertible foreign exchange.”;
  - (ii) in sub-rule (2),-
    - (a) for the word, brackets and letters “and (zzy)”, the brackets, letters and word “, (zzy), (zzzd), (zzze) and (zzzf)” shall be substituted;
    - (b) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 

“Provided further that for the purposes of this sub-rule, any taxable services provided shall be treated as export of services only if-

      - (a) such service is delivered outside India and used in business or for any other purpose outside India; and
      - (b) payment for such service provided is received by the service provider in convertible foreign exchange.”;
  - (iii) in sub-rule (3),-
    - (a) in clause (i), for the word, brackets and letters “and (zzy)”, the brackets, letters and word “, (zzy), (zzza), (zzzb), (zzzd), (zzze), (zzzf) and (zzzh)” shall be substituted;
    - (b) in clause (ii), for the brackets and letter “(d)”, the brackets, letters and word “(d) and (zzzc)” shall be substituted.

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:** The principal rules were notified *vide* notification No. 9/2005-Service Tax, dated the 3rd March 2005 and published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R.151 (E), dated the 3rd March 2005.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 28/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा. का. नि. 371(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्न नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को सेनेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियमावली 2005 कहा जाए।  
(ii) यह दिनांक 16 जून, 2005 से प्रवृत्त होंगे।
2. सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 में :—  
(i) उप नियम (1) में, खण्ड(इ) में "और (IV)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ",(iv) और (v)" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;  
(ii) उप नियम (10) के लिए निम्न उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"(10) निविष्टि सेवा वितरक बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए प्रपत्र में एक अर्द्धवार्षिक विवरणी क्षेत्राधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को अर्द्धवर्ष की अवधि के बाद आने वाले माह के अंतिम दिन से पहले प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त अर्द्ध वर्ष के दौरान प्राप्त और वितरित क्रेडिट का व्यौरा होगा।"

[फा. सं. बी-1/6/2005-टी. आर. यू.]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली, अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधसारण में सा.का.नि. 600(अ) दिनांक 10/9/2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 27/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 16 मई, 2005 द्वारा किया गया और सा.का.नि.सं.311 (अ) दिनांक 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 28/2005-Central Excise (N.T.)

**G. S. R. 371(E).**— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Eighth Amendment) Rules, 2005.  
(2) They shall come into force on the 16th day of June, 2005.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 9,-

- in sub-rule (1), in clause (e), for the word, brackets and figures "and (iv)", the brackets, figures and word "(iv) and (v)" shall be substituted;
- for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-  
"(10) The input service distributor, shall furnish a half yearly return in such form as may be specified, by notification, by the Board, giving the details of credit received and distributed during the said half year to the jurisdictional Superintendent of Central Excise, not later than the last day of the month following the half year period."

[F. No. B-1/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

**Note:** The principal rules were notified *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, and published in the Gazette of India Extraordinary *vide* number G.S.R.600 (E), the 10<sup>th</sup> September, 2004 and last amended *vide* notification No. 27/2005-Central Excise (N.T.), dated the 16<sup>th</sup> May, 2005 and published *vide* number G.S.R. 311 (E), dated the 16<sup>th</sup> May, 2005.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सं. 53/2005-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 372(अ).— अभिहित प्राधिकारी, ने, यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील और मैक्सिको (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 4002 के अंतर्गत आने वाले, गोठ के रूप में एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनबीआर या संबद्ध माल भी कहा गया है), के आयात के मामले में, अधिसूचना सं0 14/ 32/ 2003-डीजीएडी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 30 मार्च, 2005 में प्रकाशित, अपनी अनंतिम जांच परिणाम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित संबद्ध माल के पाटन मार्जिन पर्याप्त है तथा न्यूनतम से अधिक है;
- घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से की हानि, कम क्षमता उपयोग तथा लाभप्रदत्ता की दृष्टि से वास्तविक क्षति होती है;
- घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध माल के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव दोनों रूपों में क्षति हुई है;

और संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध माल के आयात पर अंतिम निर्धारण होने तक, अभिहित प्राधिकारी ने अनंतिम प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है;

और अभिहित प्राधिकारी, ने उक्त अनंतिम जांच परिणाम के संदर्भ में शुद्धि पत्र सं0 14/32/2003-डीजीएडी तारीख 21 अप्रैल, 2005 जारी किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाठित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त अनंतिम निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों/क्षेत्रों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्त्वानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्त्वानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित देशों/क्षेत्रों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, वह दर पर प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करती है।

## सारणी

क्रम सं०	शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उदाय का देश	नियर्त का देश	उत्तायक	नियर्तक	राशि	माप की इकाई	कर्तव्यी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	ब्राजिल	ब्राजिल	मै० पेट्रोफलेक्स, पेट्रोफलेक्स, ब्राजिल	मै० पेट्रोफलेक्स, ब्राजिल	136.47	मी. टन	अमरीकी डालर
2	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	ब्राजिल	ब्राजिल	मै० नाइट्रोफलेक्स ब्राजिल	मै० नाइट्रोफलेक्स ब्राजिल	215.90	मी. टन	अमरीकी डालर
3	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	ब्राजिल	ब्राजिल	कोई	उपरोक्त के अलावा कोई	220.73	मी. टन	अमरीकी डालर
4	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	ब्राजिल	मैक्रिस्को के अलावा कोई	कोई	कोई	220.73	मी. टन	अमरीकी डालर
5	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	मैक्रिस्को के अलावा कोई	ब्राजिल	कोई	कोई	220.73	मी. टन	अमरीकी डालर
6	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	164.57	मी. टन	अमरीकी डालर
7	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्यूटाइन खबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाठ के रूप में	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	ब्राजिल और मैक्रिस्को के अलावा कोई	कोई	कोई	164.57	मी. टन	अमरीकी डालर

8	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्लूटाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाट के रूप में	ब्राजिल और मैक्सिको के अलावा कोई	युरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	164.57	मी. टन	अमेरिकी डालर
9	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्लूटाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाट के रूप में	मैक्सिको	मैक्सिको	कोई	कोई	304.37	मी. टन	अमेरिकी डालर
10	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्लूटाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाट के रूप में	मैक्सिको	मैक्सिको	कोई	कोई	304.37	मी. टन	अमेरिकी डालर
11	4002	एकिलो नाइट्रोइल ब्लूटाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गाट के रूप में	मैक्सिको	मैक्सिको	कोई	कोई	304.37	मी. टन	अमेरिकी डालर

2. इस अधिक्षुचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क 6 दिसम्बर, 2005 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रमाणी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:— इस अधिक्षुचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “ अवतरण मूल्य ” से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभियंत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उत्तर सीमाशुल्क ईरिक अधिनियम की द्वारा 3.धारा 3क, धारा 8क, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उदाहृत शुल्कों को छोड़कर, रसीदी सीमाशुल्क आते हैं।

(ख) प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “ विनियम दर ” वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत (i)

के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई मारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिक्षुचना में विनियमित की गई है और “ विनियम दर ” के अवधारण के लिए

सुनांगत तारीख उत्तर सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “ प्रवेश पत्र ” के प्रस्तुत करने की

तारीख होगी ।

[ फा. सं. 354/37/2005-टी. आर. यू. ]

अजय, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

No. 53/2005-Customs

**G. S. R. 372(E).**— Whereas, in the matter of import of acrylonitrile butadiene rubber (NBR) in bale form [excluding powder and carboxylated NBR] (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 4002 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, European Union [excluding Germany], Brazil and Mexico (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, *vide* its preliminary findings notification No. 14/32/2003-DGAD dated the 30<sup>th</sup> March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30<sup>th</sup> March, 2005, has come to the conclusion that -

- (i) the dumping margins of the subject goods imported from the subject countries/territories are substantial and above de-minimis levels;
- (ii) the domestic industry suffers material injury in terms of loss of market share, low capacity utilization and profitability;
- (iii) and the injury has been caused to the domestic industry both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territories.

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duties, pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas the designated authority has issued a corrigendum dated the 21<sup>st</sup> April, 2005 vide No. 14/32/2003-DGAD to the aforesaid preliminary findings;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid preliminary findings and corrigendum of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading 4002 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

Table

S.No	Heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Brazil	Brazil	M/s Petroflex, Brazil	M/s Petroflex, Brazil	136.47	MT	US\$
2	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Brazil	Brazil	M/s Nitroflex, Brazil	M/s Nitroflex, Brazil	215.90	MT	US\$
3	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Brazil	Brazil	Any	Any other than above	220.73	MT	US\$
4	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Brazil	Any excluding Mexico	Any	Any	220.73	MT	US\$
5	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Any excluding Mexico	Brazil	Any	Any	220.73	MT	US\$
6	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	EU except Germany	EU except Germany	Any	Any	164.57	MT	US\$
7	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	EU except Germany	Any other than Brazil and Mexico	Any	Any	164.57	MT	US\$
8	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Any other than Brazil and Mexico	EU except Germany	Any	Any	164.57	MT	US\$
9	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Mexico	Mexico	Any	Any	304.37	MT	US\$
10	4002	Acrylonitrile	In bale form	Mexico	Any	Any	Any	304.37	MT	US\$

		butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]								
11	4002	Acrylonitrile butadiene rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In bale form	Any	Mexico	Any	Any	304.37	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 6<sup>th</sup> day of December, 2005 and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.* - For the purposes of this notification, -

- (a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;
- (b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/37/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.